उत्तर प्रदेश ने बॉटलिंग और वितरण नेटवर्क के विस्तार के लिए कोका-कोला से महत्वपूर्ण निवेश हासिल किया

लखनऊ, 21 जनवरी, 2025:

उत्तर प्रदेश सरकार ने वैश्विक निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) के आयोजन के दौरान, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने अन्य प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कोका-कोला के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी श्री हेनरिक ब्राउन के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

इस रणनीतिक साझेदारी का लक्ष्य मून बेवरेजेज और एसएलएमजी बेवरेजेज के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कोका-कोला के बॉटलिंग प्लांट्स और वितरण नेटवर्क का विस्तार करना है। यह समझौता 2500 करोड़ रुपये से अधिक के महत्वपूर्ण निवेश को दर्शाता है, जो राज्य की औद्योगिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने और बड़े पैमाने पर नए रोजगार अवसर सृजित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने कोका-कोला के साथ हुए समझौता ज्ञापन को उत्तर प्रदेश की निवेश क्षमता, नवाचार, विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं, कोका-कोला के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी श्री हेनरिक ब्राउन ने उत्तर प्रदेश में अपने संचालन के विस्तार और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देने को लेकर उत्साह व्यक्त किया।

हस्ताक्षर समारोह के दौरान दोनों पक्षों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री प्रथमेश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री अमित सिंह और ऊर्जा संसाधन विभाग के निदेशक श्री अनुपम शुक्ला शामिल थे।

मून बेवरेजेज लिमिटेड अगले दो वर्षों (2025-26) में उत्तर प्रदेश में लगभग 700 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जबकि एसएलएमजी बेवरेजेज इस अवधि में लगभग 2000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह महत्वपूर्ण निवेश बॉटलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित होगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

अटलांटा में स्थित कोका-कोला कंपनी पेय उद्योग में एक प्रमुख कंपनी है, जो कोका-कोला, स्प्राइट, फैंटा और डाइट कोक जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों के लिए जानी जाती है। यह कंपनी 200 से अधिक देशों में काम करती है, जिनमें मेक्सिको, चीन, ब्राजील और भारत जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में सहयोग और निवेश के संभावित क्षेत्रों में विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार, जल संरक्षण पहलों में निवेश, वितरण नेटवर्क को बढ़ाना और स्थिरता कार्यक्रमों को लागू करना शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न नीतियों के तहत प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसमें पूंजी सब्सिडी, एसजीएसटी रिफंड, स्टांप ड्यूटी और बिजली शुल्क छूट जैसे अन्य लाभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य में विकास के लिए भूमि उपलब्ध है, साथ ही स्थानीय कार्यबल का प्रशिक्षण, बेहतर लॉजिस्टिक्स और परिवहन नेटवर्क तक पहुंच भी सुनिश्चित की जाती है।